सतना | बुधवार | 26 अगस्त 2026 | वर्ष 27 | अंक 353 | पृष्ठ 20 | मूल्य रु. 6.00 navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

2 एच-1बी पर 98 लाख लगेगी फीस

4 सड़क दुर्घटनाओं की चौंकाती हकीकत

9 ड्रिंक्स-चिप्स पर चेतावनी लेबल चाहती थी सरकार

10 श्रीलंका पर भारत का शिकंजा

क्रीमी लेयर फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

केंद्र ने यूपीएससी चयन में आरक्षण पर मांगी नई स्पष्टता

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 25 अगस्त. अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के क्रीमी लेयर निर्धारण से जुड़ा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 11 मार्च 2026 के फैसले के बाद शीर्ष अदालत से स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे हैं.

विवाद मुख्य रूप से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है, जिनका ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर दर्जा उनके माता-पिता की सेवा और आय के आधार पर विवादित हुआ था.

नॉन क्रीमी लेयर दर्जा पर माता-पिता की आय को लेकर हुआ विवादित

आय सीमा को आधार नहीं बनाने का है निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम रोहित नाथन मामले में कहा था कि ओबीसी क्रीमी लेयर की पहचान केवल आय की सीमा देखकर नहीं की जा सकती. अदालत ने 1993 के सरकारी कार्यालय ज्ञापन और 2004 के स्पष्टीकरण की व्याख्या करते हुए माता-पिता के पद, सामाजिक स्थिति तथा लागू मानदंडों को भी ध्यान में रखने पर जोर दिया. दो न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र की संबंधित अपीलें खारिज करते हुए प्रभावित अभ्यर्थियों के दावों पर फैसले में बताए सिद्धांतों के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया था. इस विवाद की जड़ 8 सितंबर 1993 के डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन में है.

निजी क्षेत्र से आय भी क्रीमी लेयर में थी शामिल

रोहित नाथन से जुड़े मामले में उनके पिता निजी क्षेत्र में कार्यरत थे और उनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उन्हें क्रीमी लेयर माना गया था. इसी तरह अन्य अभ्यर्थियों के माता-पिता पीएसयू अथवा दूसरे संस्थानों में कार्यरत थे. कुछ मामलों में विभाग ने वेतन को आधार बनाकर ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर का दावा स्वीकार नहीं किया. सुनवाई के दौरान सीएटी और विभिन्न हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिए थे.

कोर्ट ने दिया था समानता का हवाला

अदालत ने इसे समानता के संवैधानिक सिद्धांत से भी जोड़ा. साथ ही उसने कहा कि जिन उम्मीदवारों को फैसले में निर्धारित मानकों के अनुसार नॉन-क्रीमी लेयर पाया जाए, उनके लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पद बनाए जा सकते हैं. फैसले के अनुसार केंद्र और संबंधित विभागों को दावों पर छह महीने के भीतर कार्रवाई करनी थी. अब सरकार की नई याचिका इसी कार्यान्वयन से जुड़ी व्यावहारिकस्थिति पर स्पष्टता चाहती है.

मंत्री शाह पर नहीं चलेगा केस

कैबिनेट का निर्णय | **सुप्रीम कोर्ट से पहले सरकार से राहत**

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 अगस्त. भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान के मामले में उलझे प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को राज्य सरकार बड़ी राहत देने जा रही है. मप्र सरकार शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं देगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने शाह के खिलाफ चल रहे मामले में अभियोजन स्वीकृति के लिए राज्य सरकार से आग्रह किया था, जिसकी मंजूरी अब तक नहीं मिली है.

मंगलवार को कैबिनेट में इस संबंध में पेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे एक्स एजेंडे के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया था. इस मामले में कैबिनेट में लगभग 10 मिनट तक चर्चा हुई. इस दौरान एसीएस जीएडी द्वारा अभियोजन की स्वीकृति देने और नहीं देने की स्थिति में पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देने के बाद सहमति बनी कि मामले में मंत्री शाह कई बार सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं, ऐसे में उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की आवश्यकता नहीं है. अब राज्य सरकार इस मामले में 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रख सकती है. हांलाकि कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान मंत्री राकेश सिंह ने यह प्रस्ताव के पेश होने से इंकार किया.

10 मिनट तक चर्चा हुई कैबिनेट में मामले को लेकर

यहां बता दें कि बीते 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो पक्ष रखा गया था, उसके मुताबिक एसआईटी मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन उसे राज्य सरकार से केस चलाने की अनुमति नहीं मिली है. कोर्ट ने तब राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था.

एक नजर में

राजनाथ अगले माह जाएंगे श्रीलंका

नई दिल्ली. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 और 10 सितंबर को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे. उनकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना तथा हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करना है.

महिंद्रा फिर बने आरबीआई निदेशक; सोमनाथ की एंट्री

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड में केंद्र सरकार ने उद्योगपति आनंद महिंद्रा को चार साल के लिए दोबारा पार्ट-टाइम नॉन-ऑफिशियल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. वहीं इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस. सोमनाथ को भी बोर्ड में रखा है.

श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी खाई में गिरी, 40 घायल

ऊना. हरियाणा के पीर निगाह मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का जत्था हादसे का शिकार हो गया. उतराई के दौरान 14 टायर वाला मालवाहक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा. दुर्घटना में करीब 40 लोगों के घायल हो गए.

फर्जी डिग्री में घिरी श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी

कुलगुरू मुकेश तिवाड़ी समेत तीन गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

भोपाल, 25 अगस्त. राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी और कथित बैकडेटेड डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है.

एसओजी ने सीहोर स्थित श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के कुलपति मुकेश तिवाड़ी, परीक्षा नियंत्रक संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को गिरफ्तार किया है. तीनों को जयपुर में ले जाकर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. एसओजी के मुताबिक अब भर्ती परीक्षा में शामिल 66 अभ्यर्थियों की डिग्रियां भी जांच के दायरे में हैं. जांच में विश्वविद्यालय से कथित तौर पर बैकडेट में डिग्री जारी किए जाने के संकेत मिले हैं.

मामले की शुरुआत सांचौर के धानता गांव निवासी भारमल राम से हुई. उस पर आरोप है कि उसने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठाया था. परीक्षा पास करने के बाद उसका शारीरिक शिक्षक पद पर चयन हो गया. उसे एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. दस्तावेज सत्यापन के दौरान भारमल राम ने सीहोर विश्वविद्यालय की बीपीएड डिग्री प्रस्तुत की थी.

फॉरेंसिक जांच में पर्दाफाश

फॉरेंसिक जांच में भारमल राम के नाम से दो अलग-अलग फीस लेजर अकाउंट मिले. इनमें कई प्रविष्टियां बाद की तारीखों में दर्ज होने के संकेत मिले. एसओजी के अनुसार भर्ती परीक्षा का परिणाम 21 अक्टूबर 2022 को घोषित हुआ था, जबकि कुछ फीस प्रविष्टियां इसके बाद की तारीखों में मिलीं. इसी आधार पर तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई.

श्रीशैलम के लॉज में मिले परिवार के 5 शव

श्रीशैलम. आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्रीशैलम में एक निजी तीर्थयात्री लॉज में एक परिवार के पांच सदस्यों की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, सभी के शव लॉज के कमरा नंबर 11 में मिले. मृतकों की पहचान सुधाकर, गोगुला आदिलक्ष्मी, मल्लेश्वरी, श्रीदेवी और मणिकांठा के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक परिवार श्री सत्य साईं जिले के बत्तालापल्ली गांव का रहने वाला था.

सीएम हाउस घेरने निकले छात्रों पर पटना में लाठीचार्ज

- टीआरई-4 में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन
- पथराव में डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल

नवभारत न्यूज नेटवर्क

पटना, 25 अगस्त. बीपीएससी टीआरई-4 परीक्षा में पीटी और मुख्य परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव, नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100 प्रतिशत डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन मंगलवार को उग्र हो गया.

ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन के छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले. उन्हें रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई थी. प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर डाकबंगला तक पहुंच गए. यहां छात्रों और सीआरपीएफ जवानों के बीच धक्का-मुक्की हुई. प्रदर्शन के दौरान एक छात्र के सिर में चोट लगी, जबकि एक छात्रा बेहोश हो गई. स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. पानी की बौछार के बीच कुछ छात्र शैंपू लगाकर नहाते हुए भी नजर आए. प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने पुलिस की ओर पत्थर फेंके. पथराव में टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह सहित कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आई. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

ड्रैगन को अरुणाचल पर डोभाल का डोज

जिनपिंग की यात्रा से पहले सीमा पर शांति को लेकर सहमति

बीजिंग, 25 अगस्त, एजेंसियां. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मंगलवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झांग से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा हुई.

डोभाल चीन के दो दिवसीय दौरे पर हैं. वह भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. इस बातचीत का मकसद सीमा पर शांति बनाए रखने और दोनों देशों के बीच पैदा हुए मतभेदों को बातचीत के जरिए कम करना है. डोभाल की यात्रा को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे की संभावना है.

सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा

भारतीय दूतावास के मुताबिक, अजित डोभाल और हान झांग की बैठक में सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता मजबूत करने पर जोर दिया गया. इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर भारत-चीन सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई. दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.

डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए : पीएम मोदी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 25 अगस्त. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के 10 साल पूरे हो गए. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की इस डिजिटल भुगतान क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यूपीआई की शुरुआत भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास में अब तक का सबसे निर्णायक क्षण साबित हुई है.

'एक्स' पर कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है. उन्होंने यूपीआई के व्यापक पैमाने और पहुंच पर गर्व करने की बात कही. प्रधानमंत्री ने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने की अपील की. उन्होंने लोगों से यह बताने को कहा कि यूपीआई के आने से उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आया है और डिजिटल भुगतान ने रोजमर्रा के लेनदेन को कितना आसान बनाया है.

एक दशक में यूपीआई से 13,000 गुना बढ़े लेनदेन

यूपीआई पर वार्षिक लेनदेन की संख्या बीते एक दशक में करीब 13,000 गुना बढ़ी है. वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेनदेन हुए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में यह संख्या 1.78 करोड़ थी.

लेनदेन का मूल्य करीब 4,000 गुना बढ़ा

वित्त वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर 314 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में कुल लेनदेन मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए था. यह एक दशक में करीब 4,000 गुना की वृद्धि को दर्शाता है.

25 अगस्त 2016 को हुआ था लॉन्च

एनपीसीआई ने 25 अगस्त 2016 को यूपीआई लॉन्च किया था. एक दशक में छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी द्वारा इसके इस्तेमाल के साथ बड़े पैमाने पर भरोसे का आधार भी बन गया है.

राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर रोक

गेट से 50 मीटर तक नहीं बिकेंगे

नवभारत न्यूज

जयपुर, 25 अगस्त. राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य के स्कूलों में जंक फूड की बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अदालत ने विद्यालय परिसरों के साथ-साथ मुख्य द्वार से 50 मीटर तक के क्षेत्र में ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.

इस दायरे में स्कूल कैंटीन और आसपास की दुकानों में मिलने वाले अधिक वसा, चीनी और नमक वाले उत्पाद भी शामिल होंगे. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और विकास से जुड़े पहलुओं पर चिंता जताई. अदालत ने स्कूलों के भीतर तथा आसपास उपलब्ध अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की बिक्री पर सख्ती बरतने की जरूरत बताई. इसके साथ ही विद्यार्थियों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई.

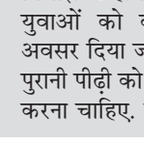

अदालत ने संबंधित स्कूलों को निर्देश दिया है कि परिसर में ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं. आदेश विद्यालय के मुख्य गेट के आसपास 50 मीटर क्षेत्र में होने वाली बिक्री पर भी लागू होगा. जिला मजिस्ट्रेट और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को प्रत्येक महीने औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. इन जांचों के जरिए यह देखा जाएगा कि विद्यालयों तथा निर्धारित क्षेत्र में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री तो नहीं हो रही है.

सीटीईटी परीक्षा स्थगित

नई दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 22वें संस्करण में बड़ा बदलाव किया है. 6 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है और संशोधित तारीख बाद में घोषित की जाएगी. इसी बीच बोर्ड ने उन योग्य उम्मीदवारों को फिर से आवेदन करने का अवसर दिया है, जो पहले निर्धारित अवधि में फॉर्म नहीं भर पाए थे. आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर 2026 तक चलेगी.

- आवेदन विंडो फिर खुली

बांके बिहारी मंदिर में दान की हेराफेरी मामला सुको पहुंचा

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 25 अगस्त. सुप्रीम कोर्ट में बांके बिहारी मंदिर की प्रबंधन समिति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दान की रकम में कथित अनियमितता का मुद्दा सामने आया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने हाई पावर कमेटी की स्टेटस रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखी. उन्होंने मामले की गंभीरता बताते हुए कुछ तस्वीरें भी पेश कीं. अदालत को एक वीडियो के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें कथित तौर पर तीन लोग दानपात्र के पास खड़े होकर श्रद्धालुओं से रुपये लेते और उन्हें पॉलीथीन की थैलियों में रखते दिखाई दे रहे हैं. इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में चढ़ावे की रकम जमा करने की प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट व्यवस्था तय करने को कहा.

सियासत | केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भाजपा की राजनीति में बड़े बदलाव के दिए संकेत, बयान के बाद मचा हड़कंप

युवाओं को कुर्सी सौंपने का आया समय, पुरानी पीढ़ी करे मार्गदर्शन

नवभारत न्यूज

नागपुर, 25 अगस्त. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने मंगलवार को राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी. नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने कहा कि वह अब पहले जितना काम नहीं कर सकते और जिम्मेदारियां नई पीढ़ी को सौंपने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी आगे आ चुकी है और पुरानी पीढ़ी उसका मार्गदर्शन कर रही है.

गडकरी ने अपने सार्वजनिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि वह करीब 30 वर्षों से लगातार सक्रिय हैं. इस दौरान उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे और अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाईं. उन्होंने कहा कि अब युवाओं को काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए और पुरानी पीढ़ी को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए. उन्होंने कहा हर पीढ़ी का एक दौर होता है. हम भी कभी नई पीढ़ी में शुमार थे और तक हमें भी जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं. तब हमें वरिष्ठों को मार्गदर्शन मिलता था. अब हम वो समय आ चुका है जब नई सोच को अवसर देने के साथ उन्हें आगे लाया जाना चाहिए.

नबीन की नई टीम में 51 युवा चेहरों को मिला है स्थान

गडकरी की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी में हालिया संगठनात्मक बदलाव की पृष्ठभूमि में भी चर्चा का विषय बनी है. पिछले सप्ताह पार्टी ने अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की थी. 65 सदस्यों वाली इस टीम में 51 नए चेहरों को शामिल किया गया है. इसे संगठन में पीढ़ीगत बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. गडकरी ने अपने संबोधन में सार्वजनिक जीवन में लंबे अनुभव और अगली पीढ़ी की भूमिका के बीच संतुलन की बात रखी. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के आने के साथ पुरानी पीढ़ी का दायित्व उनका मार्गदर्शन करना है. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में उनके भविष्य की भूमिका को लेकर अटकलें तेज हुई हैं.

मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले चर्चा

केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं. हालांकि, गडकरी ने अपने वक्तव्य में किसी पद से हटने या मंत्रिमंडल छोड़ने की घोषणा नहीं की. उन्होंने मुख्य रूप से जिम्मेदारियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की बात कही. कार्यक्रम में गडकरी ने महाराष्ट्र में विकास कार्यों का भी उल्लेख किया.

घुसपैठ के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस

आतंकवाद से निपटने एआई का करें इस्तेमाल : शाह

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 25 अगस्त. 9वें दो दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश दिया.

शाह ने कहा कि आतंकवाद और दूसरे सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी का बेहतर इस्तेमाल जरूरी है. इसके लिए एआई की मदद बढ़ाई जानी चाहिए. सम्मेलन में देशभर से 850 से ज्यादा लोग शामिल हुए. सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने, खुफिया जानकारी साझा करने, नशीले पदार्थों पर रोक, अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने, साइबर अपराध और पाकिस्तान की ओर से चलाए जा रहे छद्म युद्ध जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

बेहतर ट्रेनिंग देने पर जोर

आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए अमित शाह ने सुरक्षा बलों को बेहतर ट्रेनिंग देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भगोड़ों को वापस लाने के प्रयास तेज किए जाएं. ऐसे लोगों के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और कानून के तहत उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने के प्रावधानों का इस्तेमाल करने को भी कहा गया.

चुस्त होगी सुरक्षा प्रणाली

सम्मेलन में आसमान के निचले हिस्से में काम करने वाली प्रणालियों से पैदा होने वाले खतरों और उनसे बचाव के तरीकों पर चर्चा हुई. इसके अलावा समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा, सूचना युद्ध पर मंथन किया गया.